राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड
संयोजक: बैंक ऑफ इण्डिया

पत्रांक संख्या : रा॰ स्त॰ बै॰ स॰ / 2022-23/130 **दिनांक : 14.12.2022**

<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के समस्त सदस्यों को पत्र</u>

महोदय / महोदया,

विषय:- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 81वीं त्रैमासिक (सितम्बर 2022) समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

कृपया दिनांक 17.11.2022 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 81वी॰ त्रैमासिक बैठक का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त बैठक की कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही रिपोर्ट आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है,साथ ही हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की वेबसाइट (www.slbcjharkhand.org) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें दिनांक 31 दिसम्बर 2022 प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इनका समावेशन किया जा सके।

भवदीय,

उप महाप्रबंधक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संगलन:- उपरोक्त अनुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक: १७.११.२०२२
स्थान– होटल रेडिसन ब्लू

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 81वीं त्रैमासिक बैठक के कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 81वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक १७ नवम्बर २०२२ को होटल रेडिसन ब्लू , राँची के GBR सभागार में आयोजित की गयी। राज्य स्तरीय बैठक में झारखंड सरकार के माननीय वित्त मंत्री, डॉ रामेश्वर उरांव मुख्य अतिथि के रूप मे शामिल हुए। भारतीय रिजर्व बैंक, रांची क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक श्री संजीव सिन्हा ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-झारखंड के बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव, श्री अजय कुमार सिंह,भा॰प्र॰ से॰, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,झारखंड सरकार, श्री प्रशांत कुमार, भा॰प्र॰ से॰, एसएलबीसी झारखंड के संयोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री बिक्रम केशरी मिश्र, केनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री हितेश गोयल सहित अन्य सभी बैंकों के राज्य प्रमुख तथा सभी २४ जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक साथ ही केंद्र/राज्य सरकार के अन्य विभागों के वरीय अधिकारीगण बैठक में उपस्थित हुए।

बैठक के क्रम मे सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न प्रमुख गणमान्य को क्रमशः अपने विचार रखने हेतु आमंत्रित किया गया,जिनकी प्रस्तुति निम्नतः की जा रही है-

क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, के महाप्रबंधक, श्री बिक्रम केशरी मिश्र का सम्बोधन-

- श्री मिश्र ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया एवं बैंकों के सितम्बर तिमाही के प्रदर्शन,अन्य नीतिगत मुद्दे एवं महत्वपूर्ण विषयो के संबंध मे सभा का ध्यान आकृष्ट किया।

- श्री मिश्र ने वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक ऋण योजना के तहत 61.57% की प्रभावशाली लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी सदस्य बैंकों की सराहना की। साथ ही श्री मिश्र ने वार्षिक ऋण योजना के विभिन्न क्षेत्रो मे सितम्बर 2022 तिमाही मे कृषि क्षेत्र मे 41.06%, एमएसएमई क्षेत्र मे 67.06%, कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मे 50.19% की उपलब्धि प्राप्त करने हेतु भी सभी सदस्यों को हार्दिक बधायी दी। साथ ही सभा को राज्य मे वर्ष दर वर्ष आधार पर कुल जमा राशि में 8.62% वृद्धि एवं ऋण में 17.84% की वृद्धि के संबंध मे जानकारी दी।
(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री मिश्र ने अपने सम्बोधन में सदस्य बैंकों से ऋण जमा अनुपात वृद्धि पर अपेक्षाकृत अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया साथ ही बैंको से 31 मार्च 2023 तक राज्य के ऋण जमा अनुपात को 50% तक ले जाने के लक्ष्य को पूर्ण करने का अनुरोध किया।

(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री मिश्र ने राष्ट्र के इतिहास और संस्कृति में आदिवासी समुदाय के योगदान को काफी अहम बताते हुए बताया कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर सम्पूर्ण राष्ट्र मे दिनांक 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस मनाये जाने की जानकारी दी,साथ ही इस संदर्भ में सदस्यो को राज्य मे जनजातीय समुदायों के उत्थान हेतु राज्य के बैंकों द्वारा अब तक कुल 8.93 लाख एसटी/एससी लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं

के तहत ऋण प्रदान किए जाने की जानकारी साझा की एवं इस अवसर पर उन्होने बैंकों से अपील किया कि राज्य में आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बड़े पैमाने पर सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास करें।

(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- महाप्रबंधक एसएलबीसी ने सितम्बर,२२ तिमाही के दौरान 1.81 लाख नए केसीसी वितरित किए जाने तथा 52,290 नए एसएचजी मे क्रेडिट लिंकेज स्थापित करने के लिए सभी बैंकों को धन्यवाद दिया। श्री मिश्र ने केसीसी और एसएचजी के अतिरिक्त बैंकों द्वारा डेयरी, मत्स्य पालन, बकरी पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों में राज्य के किसानों को दिये जा रहे ऋण को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया। श्री मिश्र ने बताया कि इस तिमाही तक राज्य के बैंको द्वारा कुल 21.39 लाख मुद्रा ऋण वितरित किए जा चुके है साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी 37,011 स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित किया जा चुका है।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री मिश्र ने राज्य में बैंकिंग नेटवर्क विस्तार, आर्थिक और वित्तीय समावेशी विकास को राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया। इस संबंध में, उन्होने वित्तीय सेवाए विभाग के निर्देशानुसार उपस्थित सदस्य बैंकों से राज्य में ब्रिक एंड मोर्टार शाखाएं खोलने की प्रक्रिया का तीव्र करने तथा दिनांक 31.12.2022 से पहले सभी स्थानों पर नयी शाखा द्वारा बैंकिंग सुविधाए प्रदान करने का अनुरोध किया,साथ ही माननीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता मे आयोजित विशेष एसएलबीसी की बैठक मे मौजूदा वित्तीय वर्ष मे सरकारी एवं ग्रामीण बैंकों द्वारा 76 नयी शाखाये एवं प्राइवेट बैंकों की 50 नयी शाखाओ बैंक की स्थापना हेतु किए गए प्रयासों से एसएलबीसी को अवगत कराने का आग्रह किया।

(एक्शन-समस्त बैंक)

- श्री मिश्र ने अंत मे समस्त बैंकों के राज्य प्रमुखो से गत वर्ष की भाँति वार्षिक ऋण योजना के अनुसार राज्य मे क्रेडिट विस्तार को बढ़ावा देने के प्रयास,राज्य मे बैंकिंग सुविधावों का विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षा के ताने-बाने को और अधिक मजबूत करने का आग्रह किया।

(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)

ख) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के उपमहाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार का सम्बोधन-

- श्री सुबोध कुमार ने अपने सम्बोधन मे झारखंड राज्य के सदस्य बैंकों द्वारा वर्ष 2022-23 की पहली दो तिमाहियों के दौरान वार्षिक ऋण योजना के तहत 36.64 हजार करोड़ रुपये प्राथमिकता क्षेत्र हेतु आवंटित किए जाने की जानकारी दी तथा सितम्बर 2022 तिमाही तक कुल 18.39 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य (लगभग ५०%) हासिल किए जाने एवं गैर-प्राथमिकता क्षेत्र मे 25.00 हजार करोड़ रुपये के कुल लक्ष्य के विरुद्ध रुपये 19.56 हजार करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए जाने की जानकारी दी।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने अपने वक्तव्य मे बताया कि, बैंक न केवल अपनी शाखा नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे है, बल्कि "Village Adoption Program" के माध्यम से भी वित्तीय समावेशन और क्रेडिट संतृप्ति के तहत अपने कवरेज को बड़े पैमाने तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त कार्यक्रम के संबंध मे सभी सदस्यों को बताते हुए श्री कुमार ने 1,863 गांवों का ज़िक्र किया तथा सभा

को राज्य के1,466 गांवों को वित्त तथा सामाजिक सुरक्षा द्वारा शत प्रतिशत संतृप्त किये जाने की जानकारी प्रदान की। श्री कुमार ने सभी बैंकों से शेष गांवों को भी दिसम्बर, 2022 तक संतृप्त करने का आग्रह किया।

(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)

श्री कुमार ने एसएलबीसी झारखंड की कुछ चुनौतियों से सभा को अवगत कराया:-

- श्री कुमार ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में सदन को अवगत कराते हुए बताया की राज्य के कुछ प्रमुख बैंक अपनी वार्षिक ऋण योजना के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे है,श्री कुमार उन सभी बैंकों को वार्षिक ऋण योजना पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने एवं आगामी तिमाही मे प्रदर्शन में सुधार करने का आग्रह किया।
- डीजीएम एसएलबीसी ने आगे बताया की राज्य के 16 बैंक और 17 जिलों का ऋण जमा अनुपात 40% से कम है, इस संबंध मे बैंकों तथा ज़िलों के प्रदर्शन मे सुधार हेतु व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बतायी।
- उन्होने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से राज्य मे बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों मे वसूली हेतु परस्पर सहभागिता की आवश्यकता बतायी एवं SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत संपत्तियों के भौतिक कब्जे के लिए ज़िले मे लंबित मामलों तथा Certificate Officer कार्यालय मे लंबित मामलों के निबटारे हेतु राज्य सरकार को सहयोग एवं विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।
- इनके अतिरिक्त श्री कुमार ने औद्योगिक पार्क/एग्री पार्क/इन्फ्रा परियोजनाओं इत्यादि नीतियों में राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सुधार करने की आवश्यकता बतायी जिससे बैंक, राज्य के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास हेतु ज्यादा से ज्यादा ऋण प्रवाह मे सहभागिता कर सकें।

(एक्शन-समस्त बैंक ,एलडीएम एवं राज्य सरकार)

इसके पश्चात डीजीएम एसएलबीसी,श्री कुमार ने विगत तिमाही के दौरान विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओ के महत्वपूर्ण प्रदर्शन के बारे में सदन को अवगत कराया:

- एसएलबीसी झारखंड को पीएफआरडीए द्वारा संचालित एपीवाई सिटीजन चॉइस अभियान, 1st H1 के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की जानकारी दी, साथ ही अटल पेंशन योजना का ज़िक्र करते हुए श्री कुमार ने बताया कि योजना के तहत कुल राज्य मे कुल 2.39 लाख नामांकन के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध, 30.09.2022 तक योजना में कुल 2.17 लाख व्यक्तियों को नामांकित किये जाने की जानकारी दी।
- श्री कुमार ने एसएलबीसी के अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रति माह दो क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन की रणनीति का ज़िक्र किया तथा उन्होने योजना के महत्व के बारे मे भी सदन को अवगत कराया।श्री कुमार ने जिला स्तरीय विशेष के.सी.सी. अभियान के अंतर्गत पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने हेतु जिलों में विशेष शिविर लगाकर आवेदन सृजन एवं उनके निपटारे हेतु किए गए उपायों से भी सदन को अवगत किया ।

- श्री कुमार ने एलडीएम सहित बैंकों के राज्य प्रमुखों से केसीसी क्रॉप लोन मे राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे 3% अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन के बारे में जागरूकता फैलाने का विशेष आग्रह किया।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

श्री कुमार ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सभी सदस्य बैंको की तरफ से सदन को आश्वस्त किया कि राज्य के समग्र विकास में सभी संबंधित निकायों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,झारखंड द्वारा भरपूर समर्थन और सहयोग दिया जाएगा साथ ही एसएलबीसी भविष्य में भी अपनी प्रमाणिक भूमिका, नवऊर्जा तथा समर्पण के साथ निरंतर अग्रसर भूमिका अदा करेगा।

अंत में उप महाप्रबंधक ने एसएलबीसी के सभी सदस्यों, एलडीएम, सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों को उनके निरंतर सहयोग एवं समर्थन के लिए धन्यवाद दिया साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक , नाबार्ड और एलडीएम को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद ज्ञपित किया।

ग) नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री बिनोद कुमार बिष्ट का सम्बोधन-

- मुख्य महाप्रबंधक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के मंच को सभी सदस्य बैंकों के लिए अति महत्वपूर्ण मंचों में से एक बताया तथा तथा मंच के उद्देश्य के विषय पर प्रकाश डाला।
- मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने सदन को राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति से अवगत कराया । उन्होने राज्य के 226 प्रखंडों एवं 22 ज़िलों मे घोषित सुखाड़ का ज़िक्र किया एवं बैंकों को संबन्धित ज़िले मे प्रभावित किसानों को समस्त ऋण सुविधाये प्रदान करने का विशेष आग्रह' किया। **(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)**
- मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने पशुपालन व मत्स्य पालन हेतु बैंकों द्वारा निर्गत केसीसी के आँकड़ो पर चिंता जतायी एवं इन विषयों पर सभी बैंकों को इन योजनाओ मे ऋण प्रदान करने का विशेष आग्रह किया।

(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- मुख्य महाप्रबंधक ने वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि के संबंध मे सदन को योजना के सूक्ष्म स्तर तक देखने की आवश्यकता बतायी जिससे जिन बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम है उन बैंकों के प्रदर्शन की निगरानी की जा सके एवं प्रदर्शन मे सुधार हेतु समुचित उपाय किए जा सके।

(एक्शन-समस्त बैंक)

- Agriculture Term Loan के विषय में मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने बैंकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की, हालाँकि निजी और छोटे वित्त बैंकों द्वारा Agriculture Term लोन मे एसएलबीसी को प्रेषित रिपोर्टिंग मे स्पष्टता लाने का आग्रह किया। **(एक्शन- निजी क्षेत्र और छोटे वित्त बैंक)**
- श्री बिष्ट ने कुछ ज़िले जिनके ऋण जमा अनुपात 30 प्रतिशत से भी कम है वे ज़िले विशेषकर पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, चतरा, जामताड़ा और गुमला में स्थित सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपने ऋण जमा अनुपात मे सुधार के व्यापक प्रयास करने का अनुरोध किया, साथ ही एसएलबीसी से आग्रह किया कि वे अग्रणी ज़िला प्रबंधकों एवं जिला समन्वयकों को अपने ऋण जमा अनुपात के मौजूदा स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने मे उनका सहयोग प्रदान करें।

(एक्शन- बैंक और उल्लिखित एलडीएम)

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने पिछले तीन महीने के दौरान राज्य में नाबार्ड द्वारा किए गए विशेष कार्यों के बारे में सदन को जानकारी दी। उन्होंने सदन को सूचित किया कि RIDF के तहत नाबार्ड ने राज्य मे 2000

करोड़ रुपये की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है और इस वर्ष भी RIDF के अंतर्गत लगभग 600 करोड़ रुपये जारी किए हैं।उन्होंने बताया कि नाबार्ड द्वारा प्रदत्त इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से राज्य के कृषि और सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने सदस्यों को बताया कि पिछले वर्ष नाबार्ड ने दुमका जिले में "मसालिया मेगा सिंचाई परियोजना" हेतु 1,240 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक परियोजना को मंजूरी दी है जो लगभग 27,500 हेक्टेयर भूमि मे सिचाई व्यवस्था प्रदान करेगी साथ ही बैंकों को भी वित्त पोषण हेतु विशेष अवसर मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि नाबार्ड ने इस वर्ष देवघर और जामताड़ा ज़िले मे "सिकटिया मेगा सिंचाई परियोजना" को मंजूरी दी है जिससे लगभग 193 गांवों और 22,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को परियोजना का लाभ मिलेगा.

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- नाबार्ड ने सदन को सूचित किया कि जेएलजी वित्त पोषण राज्य मे धीरे-धीरे वृहत आकार ले रहा है, इस योजना के तहत कुछ बैंक काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। नाबार्ड ने विशेष रूप से JRGB और सहकारी बैंक एवं वाणिज्यिक बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस योजना के तहत वित्त पोषण की अगुवाई के लिए बधाई दी साथ ही अन्य बैंको को भी जेएलजी वित्त पोषण कों आगे बढ़ाने मे नाबार्ड को सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। **(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**
- श्री बिष्ट ने राज्य मे मतस्य पालन को राज्य मे विस्तार हेतु नाबार्ड द्वारा समर्थित एक अभिनव बैंकिंग योजना की जानकारी दी श्री बिष्ट ने बताया कि योजना के अंतर्गत राज्य के 7-8 बैंक केज फिश फार्मिंग और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का वित्तपोषण कर सकते हैं, साथ ही आगामी दो वर्षों के लिए नाबार्ड ने लगभग 1,100 केज फिश कल्चर और 350 बायोफ्लोक यूनिट हेतु बैंकिंग योजना बनायी है। उन्होंने एसएलबीसी, बैंकों और एलडीएम को इस गतिविधि का समर्थन करने का आग्रह किया।

(एक्शन-एसएलबीसी, समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- नाबार्ड ने सदन को जानकारी दी कि भारत सरकार की केन्द्रीय योजना के अनुसार 63,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। उन्होने बताया कि झारखंड राज्य में कुल 4,400 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में प्रारंभिक 1,500 PACS को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। श्री बिष्ट ने PACS को आगामी वर्षों में राज्य मे और जीवंत होने की संभावना बतायी।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- नाबार्ड ने बैंकों को सूचित किया कि वित्तीय समावेशन को और प्रबल बनाने हेतु राज्य के बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदत्त वित्तीय समावेशन निधि का लाभ उठा सकते हैं, उन्होंने कहा कि विगत वर्षों मे कुछ बैंकों ने योजना के तहत नाबार्ड द्वारा प्रदत निधि का लाभ उठाया भी है एवं अब तक नाबार्ड द्वारा राज्य मे 7,000 वित्तीय एवं डिजिटल समावेशन कार्यक्रमों के लिए 7 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है। नाबार्ड ने अन्य हितधारकों से भी नाबार्ड के वित्तीय समावेशन कोष का लाभ उठाने का आग्रह किया।

(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री बिष्ट ने कृषक उत्पादक संगठन पर सदन को संक्षिप्त जानकारी प्रदान की,उन्होंने बताया कि बैंकों के पास एफपीओ को वित्तपोषित कर किसानों को बड़े कर्ज देने का अवसर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि एफपीओ का वित्तपोषण छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी काफी हितकारी है। श्री बिष्ट ने एफपीओ के वित्तपोषण में

JRGB और SBI द्वारा किए प्रयासों की सराहना की और हितधारकों को सूचित किया कि बैंकों के पास इस योजना मे काफी अवसर उपलब्ध हैं उन्होने बताया कि पूरे देश में 11,000 एफ़पीओ में से 350 एफपीओ का गठन हो चुका है। नाबार्ड ने सदस्यों को जानकारी दी कि राज्य मे 350 एफपीओ में कम से कम 100 एफ़पीओ काफी अच्छे हैं और इन एफपीओ को वर्ष मे Working तथा fixed capital की आवश्यकता होती है। अतः बैंकों को एफ़पीओ को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले मे कम से कम 2-3 एफपीओ के वित्तपोषण का आग्रह किया।

(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)

घ) सचिव ग्रामीण विकास, झारखंड सरकार श्री प्रशांत कुमार का सम्बोधन

- श्री कुमार ने सभी सदस्यों का अभिवादन किया एवं दिनांक 11 नवम्बर 2022 को आयोजित एसएलबीसी उपसमिति की बैठक मे उल्लेखित मुद्दों से सभा को अवगत कराया, सचिव ग्रामीण विकास ने बताया कि जेएसएलपीएस द्वारा राज्य मे लगभग 35 एफपीओ को विभाग द्वारा पोषित किया गया है, इन पैंतीस एफपीओ में से बैंकों द्वारा, नौ एफपीओ का वित्तपोषन किया जा चुका है,श्री कुमार ने एफ़पीओ वित्त पोषण मे बैंकों को राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग देने का आश्वाशन दिया।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने SHG ऋण वितरण के तहत इस वित्तीय वर्ष मे हासिल लक्ष्य की सराहना की और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को ससमय प्राप्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि SHG ऋण वितरण में अब तक कुल लक्ष्य का 62.37% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। श्री कुमार ने सदस्य बैंकों को एसएचजी के बचत खातों पर विशेष ध्यान देने एवं सभी बचत खातो मे क्रेडिट LINKAGE करने का आग्रह किया।

(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- सचिव ने बैंक सखी को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के रूप में नियुक्त करने के विषय मे जेएसएलपीएस द्वारा चयनित 1,813 बैंक सखियों को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के रूप मे नियुक्ति किए जाने पर संबन्धित बैंकों द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बतायी। **(एक्शन-समस्त बैंक)**
- श्री कुमार ने RSETI की उपलब्धि के संदर्भ मे प्रायोजक बैंकों को प्रशिक्षण के गुणवत्ता,क्रेडिट LINKAGE एवं Settlement Ratio मे सुधार करने का आग्रह किया साथ ही इस कैलेंडर वर्ष के पूरा होने से पहले प्रशिक्षण के शेष प्रतिशत को भी प्राप्त करने का अनुरोध किया।

(एक्शन-समस्त RSETI प्रायोजक बैंक एवं एलडीएम)

ङ) प्रमुख सचिव वित्त विभाग श्री अजय कुमार सिंह का सम्बोधन

- श्री सिंह ने एसएलबीसी बैठक में आमंत्रित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का आभार व्यक्त किया।
- श्री सिंह ने सदन को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण बताया, उन्होंने सदन को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आबंटित कुल 1.01 लाख करोड़ रुपये के बजट का ज़िक्र किया जिसमे श्री सिंह ने बताया कि इनमे 0.57 लाख करोड़ रुपये पूरे राज्य के नियोजित व्यय के लिए आबंटित किए गए हैं।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने दूसरी तिमाही तक प्राप्त वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि हेतु बैंकों की प्रशंसा की और उम्मीद जतायी कि सभी सदस्य बैंक इस वित्तीय वर्ष हेतु आबंटित कुल वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे।
- श्री सिंह ने सदस्यों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 3,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों मे ब्रिक-एंड-मोर्टार शाखाओं द्वारा आच्छादित करने का आहवाहन किया ।उन्होने ब्रिक-एंड-मोर्टार शाखाओं की उपयोगिता एवं आवश्यकतावों पर प्रकाश डाला साथ ही राज्य के बैंकों को अंतिम-स्थान तक Business Correspondence या दूसरे तंत्र के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

(एक्शन-समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने राज्य सरकार की कल्याणकारी औद्योगिक नीति, रसद नीति, इलेक्ट्रिक वाहन नीति जैसी विभिन्न नीतियां के संदर्भ मे बताते हुए बैंकों को इन परियोजनाओं द्वारा राज्य मे उद्योगों को सहज ऋण सहायता प्रदान करने तथा इन नीतियों को सफल बनाने हेतु राज्य सरकार के साथ आने का आग्रह किया।

(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- उन्होंने स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के पहल की जानकारी प्रदान की एवं इन योजनाओ मे राज्य सरकार द्वारा दी जा रही ऋण एवं सब्सिडी की जानकारी भी साझा की।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- उन्होंने झारखंड राज्य के छात्रों को राज्य सरकार की पहल पर प्रदान किए जाने वाले शिक्षा ऋण के बारे में भी सदन को जानकारी दी, उन्होंने कहा कि राज्य मे 15.00 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर राज्य सरकार द्वारा गारंटी की सुविधा प्रदान की जा रही है, एवं इस ऋण पर छात्रों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज दर के आधार पर ऋण चुकाने की व्यवस्था की जाएगी।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- प्रधान सचिव, वित्त विभाग ने सदस्य बैंकों से सरकारी निगमों को विशेष रूप से जेबीवीएनएल, जेयूवीएनएल जैसे बिजली निगमों को क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया,श्री कुमार ने हाल मे खाद्य निगम को बैंकों द्वारा 1,000 करोड़ के क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि भविष्य मे राज्य सरकार इन निगमों के लिए गारंटी प्रदान करेगी और यदि निगम ऋण चुकाने में विफल रहता है तो राज्य सरकार बकाए ऋण को ब्याज सहित चुकाने मे हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार राज्य सरकार की तरफ से वित्त विभाग, बैंकों और निगम के साथ त्रिपक्षीय समझौता करने के लिए तैयार है ताकि बैंक, प्रदान की गई क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान के संबंध में पूर्णतः आश्वस्त रहें।

(एक्शन-समस्त बैंक)

- उन्होंने पिछले 4-5 वर्षों के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में विशेष रूप से आईटी क्षेत्र मे क्रांतिकारी परिवर्तनों के विषय के संबंध मे सदन को जानकारी दी एवं बताया कि आईटी क्रांति को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार भी अपनी योजनाओं के वितरण तंत्र मे परिवर्तन कर सरकारी योजनावों को प्रभावी एवं और अधिक कुशलता से लागू करने की दिशा मे अग्रसर है।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने बैठक मे अपने विचार रखते हुए हितधारकों को बताया कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है तथा जिस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत 2024 तक निश्चय

ही 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उन्होने बताया की झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष लगभग 6-7% की दर से बढ़ रही है जो देश के वार्षिक विकास दर के बराबर है। उन्होंने सदस्यों को कहा कि अगर बैंक तथा सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें तो राज्य के आर्थिक वृद्धि पर निश्चित रूप से अनुकुल प्रभाव पड़ेगा।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

च) भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), श्री संजीव सिन्हा का सम्बोधन

- श्री संजीव सिन्हा ने अपने सम्बोधन को तीन श्रेणीयों मे विभाजित किया-

पिछली एसएलबीसी बैठक से बैंकिंग और राज्य का विकास:

- श्री सिन्हा ने राज्य के बैंकों के क्रेडिट में वर्ष –दर- वर्ष ऋण वृद्धि ,राज्य के ऋण जमा अनुपात मे आयी वार्षिक वृद्धि, कृषि अग्रिमों मे वृद्धि तथा एमएसई ऋण वृद्धि पर प्रश्नता ज़ाहिर की। वार्षिक ऋण योजना में सितंबर 2022 तक 2022-23 के लक्ष्य के विरुद्ध 61.57% की उपलब्धि के संकेत, राज्य के आर्थिक विकास, विशेष रूप से महामारी के बाद के व्यवधान को सुविधाजनक बनाने मे बैंकों की अहम भूमिका बतायी। हालाँकि, सितंबर 2021 की तुलना में एमएसई क्षेत्र के कुल ऋण में आयी गिरावट पर महाप्रबंधक ने अपनी चिंता व्यक्त की।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री सिन्हा ने मार्च 2022 और जून 2022 के बीच निष्क्रिय बीसी की हिस्सेदारी में आयी बढ़ोतरी(32% से बढ़कर 35%) पर चिंता व्यक्त की साथ ही यस बैंक के 84% निष्क्रिय बीसी को काफी चिंताजनक बताया। महाप्रबंधक ने राज्य मे निष्क्रिय व्यावसायिक प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या पर बैंकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बतायी।

(एक्शन-येस बैंक)

- आरबीआई महाप्रबंधक ने विशेष रूप से जामताड़ा, पाकुड़, सिमडेगा और गुमला जिलों में वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि 40% से कम रहने पर अपनी चिंता व्यक्त की साथ ही उन्होने जिलों की क्षमता के आधार पर बने वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि कम रहने को काफी गंभीर विषय बताया।

(एक्शन- जामताड़ा, पाकुड़, सिमडेगा और गुमला अग्रणी जिला प्रबन्धक)

इसके साथ ही उन्होने अपने भाषण के दूसरे भाग के बारे में चर्चा की अर्थात् आगे का रास्ता बताया।

- भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक ने सदन को पिछले छह महीनों में एसीपी लक्ष्यों मे पिछड़ने वाले बैंकों पर चिंता व्यक्त की एवं इनके पिछड़ने के कारणों का विश्लेषण करने और संबंधित डीसीसी में इस विषय पर परिचर्चा करने का आग्रह किया,महाप्रबंधक ने विशेष रूप से जामताड़ा, पाकुड़, सिमडेगा और गुमला जिले में क्रेडिट वृद्धि की क्षमता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति बनाने की आवश्यकता बतायी।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री सिन्हा ने समाचार पत्रों मे प्रकाशित गुमला जिले के ज़िला प्रशासन द्वारा तैयार रेशम उत्पादन के माध्यम से एक साल की आजीविका परियोजना का उल्लेख किया जिसमे उन्होने करीब 1,500 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना का ज़िक्र किया। उन्होने बताया कि यह योजना खाली पड़ी जमीनों में तसर की

किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देकर स्थायी आय सृजन का काफी अच्छा तरीका सिद्ध हो सकता है। उन्होने अन्य जिलों के एलडीएम को इस विषय को ध्यान मे रखते हुए संबंधित डीसीसी में ऐसी संभावनाओं पर चर्चा करने का आग्रह किया जिससे वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य प्राप्ति मे सहयोग मिल सके।

(एक्शन- एसएलबीसी एवं एलडीएम)

- श्री सिन्हा ने लघु वित्त बैंकों के राज्य मेअभी तक के प्रदर्शन पर चिंता ज़ाहिर की एवं उन्हे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने मे अपनी क्षमता बढ़ाने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त लघु वित्त बैंक)

- आरबीआई के महाप्रबंधक ने यस बैंक को निष्क्रिय बीसी के संबंध मे, बैंक द्वारा की गयी कृत कार्यवाही से एसएलबीसी तथा भारतीय रिजर्व बैंक,राँची को दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक सूचित करने का आग्रह किया।

(एक्शन- येस बैंक)

- आरबीआई महाप्रबंधक ने एसएलबीसी से राज्य में 22 ज़िलों मे घोषित सूखे के मद्देनजर प्राकृतिक आपदा से संबन्धित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश मे उल्लेखित निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होने अन्य उपायों के अलावा, एसएलबीसी को राहत कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक समन्वित कार्य योजना विकसित करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों का सहयोग करने और एसएलबीसी/डीसीसी द्वारा तय की गई साप्ताहिक-पाक्षिक बैठकों के लिए एक कार्यबल/ उप-समिति के गठन हेतु निर्देश दिया। श्री सिन्हा ने बैंकों को मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन से संबंधित निर्देशों के अनुपालन करने का भी आग्रह किया।

(एक्शन- एसएलबीसी)

आरबीआई महाप्रबंधक ने अपने तीसरे भाग के वक्तव्य में अंतिम एसएलबीसी बैठक की तारीख से आरबीआई नियामक पहल पर चर्चा की।

- आरबीआई ने सदन को जानकारी दी कि ग्राहकों को डिजिटल आउटरीच की जरूरतों को ध्यान रखते हुए, झारखंड राज्य में दो स्थानों पर बैंकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाईयां खोली गयी हैं। आरबीआई ने विश्वास जताया कि भविष्य मे डिजिटल बैंकिंग इकाइयां लेनदेन तथा अन्य बैंकिंग आवश्यकताओ की पूर्ति मे काफी उपयोगी सिद्ध होंगी।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री सिन्हा ने सदन को सूचित किया कि आरबीआई द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (थोक) पर एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरूवात की गयी , जिसमे भारतीय रिजर्व बैंक मे स्थित खातों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार संबंधित लेनदेन किया जा रहा है,भविष्य मे इस मुद्रा को रिटेल सेगमेंट में शामिल किए जाने की संभावनाओ पर भी अपने विचार व्यक्त किए।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री सिन्हा ने सदस्यों को सूचित करते हुए बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई इनोवेशन हब, बेंगलुरु द्वारा विकसित केसीसी ऋण के लिए एंड-टू-एंड ऑन-लाइन समाधान और त्वरित टर्न-अराउंड-टाइम प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है,श्री सिन्हा ने उक्त प्रणाली को तमिलनाडु और मध्य प्रदेश राज्य में एक पायलट कार्यक्रम के तौर पर चलाये जाने का भी ज़िक्र किया। उन्होने इस माध्यम द्वारा आवेदकों की ऑन-बोर्डिंग, अन्य आवश्यकताओं के साथ, डिजीटल भूमि अभिलेखों की उपलब्धता और ऑन-लाइन भू-अभिलेखों पर चार्ज स्थापित या सत्यापन की सुविधा पर भी प्रकाश डाला। श्री सिन्हा ने झारखंड राज्य के किसानों को भी केसीसी ऋण प्राप्ति को आसान और सुविधाजनक बनाने के तरीके तथा क्षमता निर्माण की आवश्यकता बतायी। श्री

सिन्हा ने राज्य सरकार के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे भूमि अभिलेखों के शीघ्र डिजिटलीकरण की सुविधा प्रदान करें ताकि भविष्य मे झारखंड राज्य के किसानों को भी केसीसी डीजीटलिकरण की सुविधा से जोड़ा जा सके।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- श्री सिन्हा ने बताया की आरबीआई ने Digital Lending App के कामकाज को विनियमित करने की आवश्यकता को देखते हुए डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स संचालन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं जिससे इन APPS का संचालन पारदर्शी, लेखापरीक्षा योग्य ,साथ ही ग्राहक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। श्री सिन्हा ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनियमित ऋण देने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश का प्रस्ताव लाया है , उन्होने झारखंड राज्य के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे राज्य स्तर पर इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने संबंधी प्रस्ताव पर अवश्य विचार करें।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

च) माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार डॉ. रामेश्वर उरांव का सम्बोधन

- माननीय वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने एसएलबीसी बैठक में आमंत्रण हेतु सहर्ष आभार व्यक्त किया और एसएलबीसी के सदस्य बैंकों द्वारा झारखंड राज्य मे बैंकिंग सुविधा तथा लोककल्याण कार्यक्रमों की सराहना की।
- माननीय मंत्री ने सदन को राज्य सरकार द्वारा जारी कृषि ऋण माफी योजना के दो वर्ष बीत जाने के पश्चात भी 9 लाख केसीसी खातो में से केवल 4.5 लाख किसानो के कर्ज माफ होने पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सदन को राज्य सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को सफल बनाने हेतु राज्य प्रमुखों और सभी शाखाओं को ऋण माफी योजना पर युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता बतायी।

(एक्शन- समस्त बैंक और एलडीएम)

- माननीय मंत्री ने सदन को 22 जिलों के 226 प्रखंडों के सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के मुद्दे पर सदस्य बैंकों से किसानों को राहत प्रदान कर उनके कल्याण से संबन्धित योजनाएं धरातल पर लाये साथ ही किसानों को हरसंभव मदद पहुचाने का प्रयास करें।

(एक्शन- समस्त बैंक और एलडीएम)

- अपने अंतिम वक्तव्य में माननीय मंत्री महोदय ने एसएलबीसी के सदस्यों को राजभाषा की महत्ता बताते हुए आगामी बैठकों मे हिंदी भाषा के प्रयोग को और अधिक प्रयोग मे लाने की सलाह दी।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

इस सम्बोधन के उपरांत एसएलबीसी के वरीय प्रबन्धक, श्री विभव कुमार द्वारा एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र का संचालन किया गया, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एजेंडावार विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों के प्रदर्शन तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

- श्री विभव कुमार ने अपने शुरुआती कारोबारी सत्र में राज्य में मौजूदा बैंकों के प्रदर्शन तथा अन्य मुख्य विशेषताओ से सभा को अवगत कराया ।
- श्री कुमार ने राज्य सरकार के भू राजस्व विभाग के पास पिछले कई वर्षो से लंबित मुद्दों पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया एवं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के राज्य मे क्रियान्वयन तथा बैंको को राज्य के भू अभिलेख पर ऑनलाइन चार्ज दर्ज करने की सुविधा हेतु पोर्टल की आवश्यकता से अवगत कराया।उन्होने बताया कि

एसएलबीसी द्वारा राज्य के विभागो को पत्र द्वारा निरंतर इन विषयों की आवश्यकता बतायी है किन्तु राज्य सरकार द्वारा अभी तक उपरोक्त मुद्दों को हल करने हेतु ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से राज्य के लोगों को बैंकों से आसान कर्ज दिलाने हेतु उपरोक्त मुद्दों का जल्द हल निकाले जाने का अनुरोध किया।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- श्री कुमार ने आवास उपसमिति की बैठक, राज्य सरकार के संबन्धित विभाग द्वारा तिथियों के स-समय आवंटन न होने के कारण उपसमिति के संयोजक बैंक अर्थात भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आवास उपसमिति की बैठक सितम्बर तिमाही मे नहीं होने का ज़िक्र किया एवं भारतीय स्टेट बैंक को राज्य के संबन्धित विभाग से यथाशीघ्र सामंजस्य स्थापित कर बिना विलंब बैठक करने का सुझाव दिया।

(एक्शन- भारतीय स्टेट बैंक)

- श्री कुमार ने ऋण-जमा अनुपात उप समिति की बैठक मे लायी गयी परिचर्चा के संबंध में पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा प्रखण्ड मे केनरा बैंक मे जमा 16,000 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट डिपॉज़िट को बैंक के प्रधान कार्यालय के पूल खाते में दर्शाने के संबंध मे दिये निर्देशों के अनुपालन के संबंध मे केनरा बैंक के महाप्रबंधक को अपने प्रधान कार्यालय के समक्ष मुद्दे का हल निकालने का आग्रह किया गया, साथ ही इस विषय की समुचित कार्यवाही से एसएलबीसी को दिसम्बर 22 तक अवगत कराने का निवेदन किया।

(एक्शन- केनरा बैंक)

- डीसीसी और डीएलआरसी की बैठक प्रत्येक तिमाही के 45 दिनों के भीतर आयोजित करने के संबंध मे अग्रणी जिला प्रबंधकों को बैठक मे निर्देश दिये गए साथ ही कुछ ज़िलों से बैठक के समय सीमा के अंदर नहीं आयोजित करने के संबंध मे आने वाली समस्याओं को सभा के समक्ष रखे जाने की बात कही साथ ही सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धको को ज़िला प्रसाशन के सहयोग से नवंबर माह के अंत तक डीसीसी और डीएलआरसी की बैठके बुलाने और एसएलबीसी के साथ कार्यवृत्त साझा करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त एलडीएम)

- श्री कुमार ने सदन को इस वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 76 और निजी बैंकों को 50 नई शाखाएं खुलने के संबंध मे अब तक हुई प्रगति पर चिंता ज़ाहिर की एवं सदन को अभी तक केवल 5 शाखाएं खुलने की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बैंकों को वित्तीय सेवायें विभाग, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त विषय पर निरंतर निगरानी रखे जाने के संबंध मे सदस्य बैंकों को सूचित किया।

(एक्शन- समस्त संबन्धित बैंक)

- उन्होंने सदन को बैंक तथा बैंक प्रतिनिधियों द्वारा सूदूर क्षेत्रो मे आने वाली समस्याओं जैसे सड़क संपर्क, मोबाइल नेटवर्क तथा सुरक्षा संबधित खतरे की शिकायतों को राज्य सरकार तथा जिला प्रसाशन के सहयोग से दूर करने का अनुरोध किया।

  उपरोक्त विषय पर वित्त विभाग ,झारखंड सरकार के प्रधान सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए सदन को बताया कि जिन स्थानों पर बैंक शाखायें कार्य कर रही है या नयी शाखायें खोलने का प्रस्ताव है एवं यदि वहाँ सड़क संपर्क, परिसर से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो संबंधित बैंक ऐसी सूची विभाग को उपलब्ध कराये ताकि अगले 1-2 वर्ष में विभाग द्वारा समस्याओ को दूर किया जा सके। उन्होने आगे बताया कि यदि किसी बैंक को नयी शाखा हेतु परिसर की आवश्यकता है तो वे पंचायत भवन में भी अपनी शाखायें खोल सकते हैं। श्री सिंह ने राज्य सरकार द्वारा बैंकों की उपरोक्त समस्या को दूर करने का भरपूर प्रयास किये जाने का आश्वाशन दिया।

(एक्शन- एसएलबीसी और समस्त बैंक)

- ❖ श्री अजय कुमार सिंह ने एसएलबीसी से प्रत्येक पंचायत मे स्थापित बैंकिंग शाखायें या बीसी पॉइंट के मानचित्रण की जानकारी आगामी बैठक मे प्रदान करने तथा यदि किसी पंचायत मे यदि बैंकिंग सुविधाए उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हे चिन्हित करने का अनुरोध किया। उन्होंने अगली एसएलबीसी की बैठक से पूर्व इस कार्य को पूर्ण करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- एसएलबीसी)

- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक ऋण योजना मे खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों के साथ एसएलबीसी को एक बैठक आयोजित कर वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने मे आ रही समस्यावों के निदान पर चर्चा करने को कहा।

(एक्शन- एसएलबीसी)

- ❖ अंत में श्री बिभव कुमार ने बैंको के प्रतिनिधियों से किसी मुद्दे या सलाह पर चर्चा करने हेतु सदन मे आमंत्रित किया, जिस पर केनरा बैंक के प्रतिनिधि श्री रामचंद्रन ने RSETI के प्रदर्शन के मुद्दे पर सदस्यो को उम्मीदवार के चयन के वक़्त, निदेशक ,RSETI को उम्मीदवार के पास बचत यदि बचत खाता उपलब्ध नहीं है तो बचत खाता खुलवाने तथा प्रशिक्षण उपरांत जन समर्थ पोर्टल पर ऋण आवेदन अपलोड करने की सलाह दी जिससे आवेदन की अस्वीकृति या पेंडिंग की समस्या का निवारण किया जा सके। उपरोक्त सुझाव पर भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक ने भी अपनी सहमति जतायी एवं प्रायोजक बैंकों को राज्य के RSETI निदेशकों को इस संदर्भ मे उचित दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त एलडीएम)

- ❖ निदेशक, पशुपालन ने हर जिले में गायों के वित्तपोषण के लिए सभी एलडीएम को समस्त लाभुकों की सूची प्रदान किए जाने की जानकारी प्रदान की तथा उन्होने इन लाभुकों कों आरसेटी के प्रशिक्षण कार्यक्रम मे शामिल करने का सुझाव दिया, जिससे पशुपालन को राज्य मे आय सृजन हेतु और अधिक व्यापक बनाया जा सके।

(एक्शन- एलडीएम / निदेशक RSETI)

- ❖ राज्य निदेशक, आरसेटी ने पशुपालन एवं मत्स्य विभाग से अनुरोध किया कि जिन लाभार्थियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनकी सूची राज्य निदेशक, आरसेटी को उपलब्ध कराए जिससे RSETI द्वारा ऐसे सभी लाभार्थियों को एक माह के अंदर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए जा सके।

(एक्शन- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग)

अंत में, केनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री हितेश गोयल ने एसएलबीसी की 81वीं बैठक में शामिल सभी सदस्यों तथा मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को बैठक की परिचर्चा मे शामिल होने हेतु धन्यवाद दिया।

(बिक्रम केशरी मिश्र)
महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

उपस्थिति लेखा

81वीं एसएलबीसी बैठक, सितम्बर 2022

17 नवम्बर होटल रेडिसन ब्लू, कडरू बाई पास रोड

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
1	डॉ रामेश्वर उरांव	माननीय वित्त मंत्री	झारखंड सरकार	
2	श्री अजय कुमार सिंह	प्रधान सचिव वित्त	झारखंड सरकार	
3	श्री प्रशांत कुमार	सचिव ग्रामीण विकास	झारखंड सरकार	
4	श्री संजीव सिन्हा	महा प्रबंधक (ओ-आई-सी)	भारतीय रिजर्व बैंक	
5	श्री बिक्रम केशरी मिश्र	महाप्रबंधक	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
6	श्री बिनोद कुमार बिष्ट	मुख्य महाप्रबंधक	नाबार्ड	
7	श्री सुबोध कुमार	उप महाप्रबंधक	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
8	श्री हितेश गोयल	महाप्रबंधक	केनरा बैंक	9334913525
9	श्री प्रवीण कुमार सिंह	उप महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9004356910
10	श्री अमित विश्वकर्मा	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	
11	श्री नलिन प्रियरंजन	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	
12	श्री एच एन द्विवेदी	निदेशक मत्स्य	मत्स्य विभाग	
13	श्री एमडी आफताबुद्दीन	सहायक महाप्रबंधक	नाबार्ड	
14	श्री सुबोध कुमार	उप महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	9001500222
15	श्री अरविंद कालरा	सहायक महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	
16	श्री बिश्वजीत कुमार सिन्हा	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	7718825815
17	श्री हेमंत कुमार तिवारी	सहायक महाप्रबंधक	यूको बैंक	9476492047
18	श्री वी के मौर्य	महाप्रबंधक	बीएसएनएल, झारखंड	9431200178
19	डॉ रमेश कुमार मोहंती	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	6287395601
20	श्री इंद्र यादव	संयुक्त निदेशक	एमएसएमई डि रांची	8126248984
21	श्री मनोज कुमार भगत	उप सचिव	उद्योग विभाग	8789032017
22	श्री पी एन त्रिपाठी	अपर निदेशक कृषि	कृषि विभाग	9431188371
23	श्री ए पी एक्का	उप निदेशक कृषि	कृषि विभाग	9431766424
24	डॉ मनोज कुमार	एमडी / सीईओ	झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	9471530929
25	श्री एमपी सुगुनन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	धनबाद सेंट्रल को-ऑप बैंक	7086240266
26	श्री एफ.आर. बुखारी	उप महाप्रबंधक	इंडियन बैंक	9051658238
27	श्री जे पी शर्मा	उप पंजीयक	आरसीएस कार्यालय रांची	9431165349
28	श्री मनीष कुमार	सहायक महाप्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	
29	श्री आलोक कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	7905445469
30	श्री नीरज कुमार	सहायक महाप्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	8390090034
31	श्री रामचंद्र	डिविजनल मैनेजर	केनरा बैंक	9430724980
32	श्री रोहित कुमार सिंह	प्रबंधक	केनरा बैंक	9844236588
33	श्री सुनील कुमार	उप महाप्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9264291876
34	श्री राजीव रंजन	वरिष्ठ प्रबंधक	इंडियन बैंक	8617763005
35	श्री राजेंद्र कुमार	मुख्य प्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	9837130924
36	श्री सागर कुमार बेहरा	सहायक महाप्रबंधक	पंजाब और सिंध बैंक	9088014691
37	श्री एच वाई बास्की	मुख्य प्रबंधक	पंजाब और सिंध बैंक	7508510730
38	श्री संजय कुमार सिन्हा	मुख्य प्रबंधक	यूको बैंक	8016710116
39	श्रीमती सोनालिका	सहायक महाप्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9845416052
40	श्री अनिल कुमार	प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9140038702
41	श्री जगन्नाथ गुप्ता	महाप्रबंधक	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	9473453102
42	श्री रवींद्र कुमार सिन्हा	सहायक महाप्रबंधक	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	8210022097
43	श्री ताहिर अजीज	शाखा प्रमुख	जम्मू और कश्मीर बैंक	9906608262
44	श्री प्रीतम सिन्हा	मंडल प्रबंधक	एक्सिस बैंक लिमिटेड	9004098940
45	श्री अभय कुमार	क्लस्टर हेड	बंधन बैंक	9534130002
46	श्री राजीव मोहंती	क्षेत्र प्रमुख	फेडरल बैंक लिमिटेड	9090909039
47	श्री नवनीत सिंह गांधी	उप उपाध्यक्ष	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9934011083
48	श्री धर्मेंद्र	उपाध्यक्ष	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	
49	श्री कौशल किशोर	सहायक महाप्रबंधक	आईसीआईसीआई बैंक लि	9934313934

50	श्री सैयद शब्बीर अख्तर	प्रबंधक	आईसीआईसीआई बैंक लि	
51	श्री ईमान संजीव तूती	सहायक महाप्रबंधक	आईडीबीआई बैंक लि	9926624415
52	श्री राज कुमार कमल	क्षेत्रीय प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9835327748
53	श्री नागराजुन	एसएलएम	इंडसइंड बैंक	
54	श्री मयंक	एलएम	इंडसइंड बैंक	
55	श्री किरण मिश्रा	मुख्य प्रबंधक	कोटक महेंद्र बैंक लिमिटेड	9163545333
56	श्री राजेश कुमार	सहायक शाखा प्रबंधक	कर्नाटक बैंक	7549150009
57	श्री जाहिद जहीर	सहायक मैनेजर	डीबीएस बैंक	
58	श्री बादल झा	शाखा प्रमुख	साउथ इंडियन बैंक	9560410781
59	श्री शिशिर सारंगी	सहायक उपाध्यक्ष	यस बैंक	7763803332
60	श्री दिलशाद अली	कुंजी खाता प्रबंधक	फिनो पेमेंट्स बैंक	7781007059
61	श्री वी. विजय कुमार	शाखा प्रमुख	करूर वैश्य बैंक	7091194716
62	श्री स्नेह सौरव	क्लस्टर हेड	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक	7250483060
63	श्री बिराज डेका	मुख्य प्रबंधक	इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक	9038224956
64	श्री नितेश श्रीवास्तव	वरिष्ठ प्रबंधक	उज्जीवन लघु वित बैंक लिमिटेड	
65	श्री अमरेंद्र झा	क्षेत्रीय देयता प्रबंधक	उत्कर्ष लघु वित बैंक लिमिटेड	9334616474
66	श्रीमती प्रियंका पांडे	वरिष्ठ शाखा प्रबंधक	जना लघु वित बैंक	
67	श्री साथियानाथन के एम	उपाध्यक्ष	ESAF लघु वित बैंक लिमिटेड	8762579551
68	श्री बिकास पाडिया	सर्किल वितरण प्रमुख	एयरटेल पेमेंट्स बैंक	9932449258
69	श्री जयशेखर प्रसाद	संबंध प्रबंधक	एयरटेल पेमेंट्स बैंक	
70	श्री विकाश कुमार	क्लस्टर हेड	पेटीएम पेमेंट बैंक	7004657014
71	श्री दीपक कुमार	एमओ	एयू लघु वित बैंक	8905100184
72	श्री राजीव कुमार सिंह	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	आरसीएस कार्यालय रांची	7004726652
73	श्री अनिल कुमार	आरसेटी	जेएसएलपीएस	9431901016
74	श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह		जेएसएलपीएस	8292977966
75	श्री संदीप सोनवणे	निर्देशक	केवीआईसी रांची	9431169393
76	श्री राजीव मल्होत्रा	सहायक निदेशक	केवीआईसी रांची	
77	श्री चंद्र भूषण पांडे	राज्य नियंत्रक	रुडसेटी की राष्ट्रीय अकादमी	9073396646
78	श्री एस बी मिश्रा	एसडीआर	नसर	9330752100
79	श्री एच पी बियानी	अध्यक्ष	जेएसआईए	8002685608
80	श्री शिवम सिंह	संयुक्त सचिव	जेएसआईए	9835334399
81	श्री विवेक कुमार	एसडीई (एसबी) बीएसएनएल	बीएसएनएल, झारखंड	
82	श्री देबदर्शी राय		एनपीसीआई	9641344120
83	श्री संजीव कुमार	एलडीएम	बोकारो	9430458214
84	श्री देवब्रत शर्मा	एलडीएम	चतरा	8002738027
85	श्री राजेश केआर सिन्हा	एलडीएम	धनबाद	8406002014
86	श्री संतोष कुमार	एलडीएम	पूर्वी सिंहभूम	7260814454
87	श्री नीतीश कुमार	एलडीएम	गिरिडीह	7903761115
88	श्री आबिद हुसैन	एलडीएम	गुमला	8451978491
89	श्री सुधाकर पांडे	एलडीएम	हजारीबाग	9407585820
90	श्री बिनय कुजूर	एलडीएम	खूंटी	8340514511
91	श्री अजय राणा	एलडीएम	कोडरमा	8789938263
92	श्री रवींद्र प्रसाद	एलडीएम	लोहरदगा	9931108187
93	श्री संजीव कुमार	एलडीएम	रामगढ़	8709551260
94	डॉ श्रीकांत	एलडीएम	रांची	9798967181
95	श्री बीरेंद्र कुमार शिट	एलडीएम	सरायकेला	9572024420
96	श्री संजीव कुमार चौधरी	एलडीएम	सिमडेगा	7903780946
97	श्री लक्ष्मी नारायण लागुरी	एलडीएम	पश्चिम सिंहभूम	8210786477
98	श्री प्रवीण कुमार	एलडीएम	दुमका	9903491709
99	श्री धर्मेश पांडे	एलडीएम	गोड्डा	7383400449
100	श्री इंदु भूषण लाल	एलडीएम	गढ़वा	9934363709
101	श्री राम कृपाल बैठा	एलडीएम	जामताड़ा	9341529204
102	श्री शांति प्रसाद टोप्पो	एलडीएम	लातेहार	7781011677
103	श्री मनोज कुमार	एलडीएम	पाकुर	9771438410
104	श्री अनुकरण तिर्की	एलडीएम	पलामू	9934363710

105	श्री सुधीर कुमार	एलडीएम	साहिबगंज	9771438409